eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

# ग्रामीण विकास पर एक अध्ययनः भारत के विशेष सन्दर्भ में

सुमित कुमार[1], प्रो० प्रीति पाठक[2]
[1]**शोधार्थी, रा**जनीति विज्ञान, साहू रामस्वरुप महिला महाविद्यालय, बरेली
[2]राजनीति विज्ञान विभाग—साहू रामस्वरुप महिला महाविद्यालय, बरेली

Received: 15 Feb 2025, Accepted & Reviewed: 25 Feb 2025, Published: 28 Feb 2025

## Abstract

ग्रामीण विकास का अर्थ है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और आर्थिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही ग्रामीण विकास कहलाता है। ग्रामीण विकास किसी देश के विकास की महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, 2011 की जनगणना के आधार पर 68.84 % लोग गांव में रहते हैं, और यदि ग्रामीण क्षेत्र का विकास धीमा रहे तो यह समग्र आर्थिक प्रगति में बाधा बनेगा। वर्षों से,भारत में ग्रामीण विकास की नीतियों, रणनीतियों और योजनाओं में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिससे इसे एक नया दृष्टिकोण और दिशा मिली है। ग्रामीण आर्थिक विकास में भिन्न—भिन्न क्षेत्रों के एकीकरण के आधार पर आवश्यक नीतियां बनती हैं, जो ग्रामीण इलाकों या क्षेत्र को सतत विकास प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करती है। इस अध्ययन मुख्य उद्देश्य भारत में ग्रामीण विकास की भूमिका महत्व मुद्दे और सरकार द्वारा उठाए गए पहलों का विश्लेषण करना है।

**मूल शब्दः** ग्रामीण विकास,रोजगार और विकास, ग्रामीण लोग

## Introduction

भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण विकास आर्थिक और सामाजिक उत्थान या प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं, जिससे यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति में देश की समग्र आर्थिक वृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह केवल आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य ,बुनियादी ढांचे, कृषि,रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण का प्रदान करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखा जाए तो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है या भारत की लगभग दो—तिहाई जनसंख्या कृषि का निर्भर है। लेकिन कुछ वर्षों से इसकी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भागीदारी घटती जा रही है। इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन, मानसून पर निर्भरता, गरीबी, संसाधनों की कमी और शोषण जैसे अनेक समस्याएं ग्रामीण विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जैसी पहल शुरू किया। जिस प्रकार इन योजनाओं का क्रियान्वयन आवश्यक है, उसी प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। प्रक्रियात्मक और दार्शनिक आधार पर विकास प्रक्रिया के लिए जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। विकास प्रशासकों को और योजनाओं के लिए विभिन्न समुदायों की सहायता ले, जिससे योजनाओं में सहभागिता बन सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत की शीर्ष संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास से

संबंधित नीतियां, नियम और कानून बनाती हैं। कृषि, हस्तशिल्प, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और डेयरी मुख्य उद्योग हैं। जो ग्रामीण व्यवसाय और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। ग्रामीण विकास जनता की भागीदारी कृषि और ग्रामीण उद्योगों को समझना है। सतत विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की संपूर्ण प्रगति का आधार है।

**ग्रामीण विकास का महत्वः** ग्रामीण विकास किसी भी देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से भारत में जहां 68.84% जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं किया जा सकता है, किंतु यह सामाजिक उत्थान, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसके महत्व को इस प्रकार से समझ सकते हैं–

- आर्थिक सशक्तिकरणः ग्रामीण विकास से कृषि, लघु उद्योग, हस्तशील, मत्स्य पालन और डेयरी जैसे क्षेत्रों के बढ़ावा से ग्रामीण लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- गरीबी उन्मूलनः ग्रामीण इलाकों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर गरीबी को काम किया जा सकता है। मनरेगा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसे विभिन्न सरकारी योजनाए इसी दिशा में कार्य करती हैं।

- शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। ग्रामीण विकास के तहत ग्राम प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाता है।

- बुनियादी ढांचे का विकासः गांव में सड़क, परिवहन, बिजली, सिंचाई और डिजिटल कनेक्टिविटी का विकास आवश्यक है,जिससे ग्रामीण इलाकों को शहरी सुविधाओं से जोड़ा जा सके।

- सामाजिक समरसता, ग्रामीण विकास, सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता को कम करने में सहायक होता है, जिससे समाज में समान अवसर मिल सके।

- सतत विकासरू पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के बिना विकास अधूरा सा रहता है। जैविक खेती, जल संरक्षण और हरित ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण विकास को पर्यावरण हितैषी बनाया जा सकता है।

अत: यह स्पष्ट हो गया है कि जनता की भागीदारी ग्रामीण विकास की सफलता के लिए आवश्यक है। यदि वृद्धि और सार्थक विकास हासिल करना है तो जनता की भागीदारी अनिवार्य है, जिससे ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास के बेहतर मार्ग प्राप्त हों सके और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।

**ग्रामीण विकास का उद्देश्यः** ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकाश से देख सकते हैं-

- रहन–सहन में सुधार, ग्रामीण समुदाय में भोजन, आवास,वस्त्र,स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।

- गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ाना, रोजगार को प्रोत्साहित करना और गरीबी की समस्या को कम करना।

- कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ग्रामीणों में कृषि के लिए नई–नई तकनीको का उपयोग बढ़ाकर उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि करना,सिंचाई,उर्वरक और आधुनिक की खेती के संसाधनों को बढ़ावा देना।

- जन भागीदारी को बढ़ावा देना, पंचायतो और स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना ताकि ग्रामीण जनता स्वयं अपनी विकास योजनाओ में भागीदारी कर सके।

- सतत विकास और पर्यावरण, जल संरक्षण,वृक्षारोपण, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक रूप से बढ़ावा देकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना।

## डाटा और कार्य प्रणालीः

इस अध्ययन में मुख्य रूप से सैद्धांतिक (थियोरेटिकल) रूप से किया गया है। अध्ययन के लिए द्वितीय डेटा (सेकेंडरी डाटा) का उपयोग किया गया है जिसमें प्रकाशित पुस्तक,शोध पत्रों,पत्रिकाओं और वार्षिक रिपोर्ट की सहायता लिया गया है।

## भारत में ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्याएं या मुद्दे–

भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक और गैर आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। ग्रामीण इलाकों का विकास को घरेलू और वैश्विक दोनों ही कारकों का प्रभाव दिखाई देता हैं।

## गैर आर्थिक समस्याएंः

- सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणः जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, और परंपरागत रीति रिवाज।
- प्राकृतिक और भौगोलिक कारकः जलवायु परिवर्तन, जल संकट,मानसून पर निर्भरता।
- राजनीतिक समस्याः प्रशासनिक बाधाएं, भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाना।

## आर्थिक समस्याएंः

- कृषि पर निर्भर, आधुनिक तकनीकी की कमी, उत्पादकता में गिरावट।
- बेरोजगारी और निम्न स्तर गैर–कृषि क्षेत्रों में रोजगार की सीमित अवसर।
- बुनियादी सुविधाओं की कमी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्धता में कमी।

अतः इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और समाज और निजी क्षेत्र को मिलकर महत्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण भारत सतत और समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सके। सरकार के मूल्यों को ग्रामीण परिवेश में समाहित करने के तत्व निम्न प्रकार हैं–

- ग्रामीण वातावरण एक जटिल और गतिशील रणनीति के रूप में।
- यह ग्रामीण जनता की संतुष्टि और निष्ठा को सुनिश्चित करता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

- ग्रामीण समाज के बदलते दृष्टिकोण को समझना और परिवर्तन करना।
- सतत विकास और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करना।
- तकनीकी बदलावों को निरंतर अपनाना और अपडेट रखना।
- उच्च तकनीकी परिशोधन और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।
- जनहित नीतियों को लागू करना।
- ग्रामीण विकास और आर्थिक वृद्धि को आपस में सामंजस्य बैठना।

**भारत में ग्रामीण विकास के लिए नवाचारी विचारः**

- स्थानीय संसाधनों का उपयोगः यदि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत (नदी, तालाब,जलाशय) उपलब्ध है,तो उन्हें सुरक्षित और पुनर्भरण करने के लिए उचित प्रकार से योजनाएं बननी चाहिए। जैसे तालाबों को गहरा करना, नए जलाशय बनाना, बाध और नहरों का निर्माण तथा जल संरचनाओं को मजबूत करना आदि। अतः इन क्षेत्र में लोहा, कोयला या ग्रेनाइट की खदान है तो उन्हें स्थानीय लोगों के लिए रोजगार उचित प्रकार से प्रदान करना चाहिए।

- ग्रामीण उद्योगों की स्थापनाः गांव में कई प्रकार के उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं, जो स्थानीय संसाधनों और श्रमिक का उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है।

- एग्रो–प्रोसेसिंग उद्योगःगांव में कृषि आधारित उद्योगों जैसे फल,सब्जी प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, दूध और दुग्ध उत्पादन आदि को बढ़ावा देना।

- हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगः ग्रामीणों में बने हस्तशिल्प, बांस उत्पाद,लकड़ी की वस्तुएं मिट्टी के बर्तन और पारंपरिक वस्त्रों और अन्य प्रकार के हस्तशिल्प शामिल है।

- इंजीनियरिंग और सेवाएंः ट्रैक्टर और पंप सेट की मरम्मत, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग जो कृ षि उपकरणों पर निर्माण करते हैं।

- सेवाएंः मोबाइल कृषि यंत्रों की सर्विसिंग आदि।

- स्टार्टअप्सः नवाचार और उद्यमशीलता की नई पहल है जो हाल ही के समय स्थापित किय गये व्यवसाय होते हैं। जिनका उद्देश्य बाजार में मौजूद किसी आवश्यकता,मांग या समस्या का समाधान करना होता है। यह सुव्यवस्थित व्यावसायिक मॉडल के आधार पर सामान सेवाएं,प्रक्रिया विकसित करते हैं,जिससे समाज और अर्थव्यवस्था को लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण– कृषि स्टार्टअप,सप्लाई चौन, लॉजिस्टिकस,कृ षि उत्पादों का व्यापार, कृषि प्रसंकरण,मस्त पालन, ग्रामीण माइक्रोफाइनेंस ग्रामीण,स्वास्थ्य ग्रामीण, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल और ग्रामीण शिक्षा आदि।

- कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाएंः कंप्यूटर प्रशिक्षण और मरम्मत सेवाएं, इंटरनेट आधारित व्यवसाय जैसे ई–कॉमर्स, रेल और बस टिकट बुकिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग आदि।

- ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देनाः ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता(म्दजमतचतमदमनतेीपच) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल अपनाएं जा सकते हैं जो इस प्रकार हैं–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

- व्यक्तिगत उद्यमिताः एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय (किराना स्टोर, डेयरी फार्म, हस्तशील निर्माण) आदि।
- समूह उद्यमिताः साझेदारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ।
- क्लस्टर उद्यमिता (Enterpreneurship in cluster formation): NGOs, स्वयं सहायता समूह(SHGs),सामुदायिक संगठन(CBOs) का नेटवर्क शामिल है। व्यवसायों जाति व्यवसाय और वित्तीय संसाधनों के आधार पर संगठित करना।
- सहकारी उद्यमिताः समान उद्देश्य के लिए स्वतंत्र व्यक्तियों का एक साथ मिलकर काम करना जैसे डेयरी सहकारी समिति और लोकप्रिय सहकारी बैंक।

**ग्रामीण विकास दृष्टिकोणः**

- भारतीय सरकार को आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और नागरिकों को रोजगार एवं व्यवसायिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रभावी नीतियां अपनानी चाहिए। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित हो सके। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में, सरकार पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने का दबाव है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावी बनाया जा सके। ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण इस प्रकार हैं–
- मानव दृष्टिकोणः ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों और श्रमिकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है,इससे वे बेहतर उत्पादन कर सके और दक्षता में वृद्धि कर सके।
- सामाजिक परिप्रेक्ष्यः ग्रामीण समाज एक ऐसा ताना–बाना है,जो परंपराओं, संस्कृति और मानवी संवेदनाओं से जुड़ा है। सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए और सरकारी विकास कार्यक्रमों को इन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए।
- आर्थिक परिप्रेक्ष्यः कोई भी अर्थव्यवस्था तभी सफल हो सकती है, जब उसकी योजनाएं उस समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाएं। ग्रामीण विकास के लिए ऐसी रणनीतिया अपनानी चाहिए जो न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करें बल्कि रोजगार सृजन, कृषि एवं छोटे उद्योगों के विकास को भी बढ़ाया दे।
- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यः देश की संपूर्ण आर्थिक प्रगति के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास अनिवार्य है। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी तो शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या और जान संसाधनों पर दबाव कम होगा। सरकार की बुनियादी ढांचे शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश करना चाहिए ताकि, ग्रामीण और शहरी विकास के बीच संतुलन बना सके।
- वैश्विक परिप्रेक्ष्यः तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण में पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया हैं,अब सरकारी नीतियों को वैश्विक मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ सके।

## भारत में ग्रामीण विकास की रणनीतियांः

- सभी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
- मानसून की विफलता, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में सरकार को किसानों की मदद के लिए तत्पर पर रहना चाहिए।
- सरकार को विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(डैच) प्रदान करनी चाहिए, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके,इसके साथ फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए।
- जो किसान वास्तव में कृषि कार्य कर रहे हैं, उन्हें के लिए सरकार को जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- किसानों को सीधे नगद सहायता देने की बजाय सरकार को उन्हें गुणवत्तापूर्ण उर्वरक, कीटनाशक और अन्य आवश्यक कृषि सामग्री मुक्त उपलब्ध करानी चाहिए ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए।
- नए कृषि गोदामो की स्थापना करना चाहिए।
- कृषि अनुसंधान और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

## ग्रामीण विकास में सरकार की भूमिका

भारत की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास आवश्यक है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू करती है। इसके तहत कृषि सुधार, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, तकनीकी विकास और गरीबी उन्मूलन जैसी पहल की जाती हैं।

आर्थिक विकास और रोजगार सृजनः सरकार कृषि और गैर–कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मनरेगा (MGNREGA), स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी योजनाएं लागू करती है।
किसानों को ऋण और सब्सिडी देकर उन्हें सशक्त बनाती है, जिससे उनकी आय बढ़े और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम (TRYSEM] DDU&GKY) लागू किए जाते हैं।
कृषि और सिंचाई सुधारः सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करती है, जिससे उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सभी खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नहरों, ट्यूबवेल और ड्रिप सिंचाई जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं।
फसल बीमा योजना (PMFBY) के जरिए प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है।
जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है।
शिक्षा और कौशल विकासः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मिड–डे मील योजना और नवोदय विद्यालय जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) लागू की गई है।

स्वास्थ्य और स्वच्छताः ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण और स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है।

बुनियादी ढांचे और डिजिटल विकासः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं।

सस्ती बिजली और जल आपूर्ति के लिए सरकार सौभाग्य योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं चला रही है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सामाजिक और महिला सशक्तिकरणः महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके।

महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

**सामुदायिक विकास कार्यक्रमः**

• Intensive Agricultural District Programme [IADP]
• Intensive Agricultural Area Programme [IAAP]
• Whole Village Development Programme [WVDP] • Drought Prone Area Programme [DPAP]
• Cash Programme for Rural Development
• Food for Works Programme [FFW]
• Small Farmers] Marginal Farmer and Agricultural Laboure*s Development Agency
• Minimum Needs Programme [MNP]
• Command Area Development [CAD]
• National Rural Employment Programme [NREP]
• Million Wells Scheme [MWS]
• Training of Rural Youth for Self&Employment [TRYESM
• Jawahar Rojgar Yojana [JRY]
• Indira Awas Yojana
• Rural Landless Employment Guarantee Programme [RLEGP]
• Development of Women and Children in Rural Areas [DWCRA]
• Employment Assurance Scheme [EAS]
• Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
• Saansad Adarsh Gram Yojana
• Mission Antyodaya
• Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

## निष्कर्ष:

भारत की आर्थिक प्रगति, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण विकास पर अत्यधिक निर्भर है। यह कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के साथ–साथ बेरोजगारी, गरीबी, प्रवासन और आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा, यह न्यूनतम पूंजी निवेश में रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है।

सरकार ने यह महसूस किया है कि आर्थिक परिवेश में हो रहे बदलावों के अनुसार संसाधनों का उचित प्रबंधन और उपयोग आवश्यक है। डिजिटल तकनीक और इंटरनेट के प्रभावी उपयोग से आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है और व्यक्ति, प्रक्रिया और तकनीक को आपस में जोड़ा जा सकता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में सरकार को नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है। यदि सरकारी योजनाओं और नीतियों को पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुसार तैयार और लागू किया जाए, तो सतत और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार दीर्घकालिक और लाभकारी नीतियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकती है। व्यवसाय, आर्थिक नीतियों और ग्रामीण विकास के संतुलन के साथ ही भारत समग्र और स्थायी आर्थिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–


- अग्रवाल, जी0 के0(1976)ः भारतीय सामाजिक संस्थायें, एस बीपीडी पब्लिगि आगरा ।
- गुप्ता, यू0सी0, वर्मा, प्रतीक (2014)ः ग्रामीण विकास परियोजना, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
- यादव, धर्मेन्द्र सिंह (2017)ः पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, रावत पब्लिषर्स।
- यादव,राम जी (2019)रूभारत में ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
- गुप्ता, यू•सी•, वर्मा (2014)रू ग्रामीण विकास परियोजना।
- Rov,p.srivasa(2019):Rural development schemes in india-A study intrnational jornal of research and analytical revivews(IJRAR),Volume06,issue 1,(E-ISSN 2348-1269,P-ISSN 2349-1538)
- https://hiim.wikipidia.org.
- https://www.census2011.co.in